market by the Indonesian Companies at prices far below their cost of production; and

(b) if so, the details of the preventing measures taken and proposed to be taken by Government to protect the domestic industry from this onslaught?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) A petition has been received by the Designated Authority only on 27.5.98 alleging dumping of float glass from Indonesia.

(b) Under the Anti-dumping laws, anti-dumping duties can be imposed only if there is evidence of dumping, injury and the casual link between the two. The Designated Authority, therefore, takes a view on initiation of a case and required investigations after receiving the necessary information from the affected industry. Anti-dumping duties can be levied if a case is established.

Delhi Rent Control Amendment Act

*73. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) by when Government propose to notify the Delhi Rent Control Amendment Act;

(b) whether amendments have been made after President's assent thereon; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) The Delhi Rent Act, 1995, as assented to by the President on 2.8.1995 has not been brought into force so far. The Government proposes to enforce the Delhi Rent Act, 1995 after effecting changes in some of its provisions.

(b) and (c) Soon after the Delhi Rent Bill, 1994 was passed by both the Houses of Parliament. Several representations demanding changes in some of the provisions were received. An All Party Committee was set up by the then Chief Minister of Delhi in June, 1995. Since the question of amending the Act was under examination of the Government, it was not brought into force. In July, 1997, it was decided by the Government to make changes in some of the provisions of the Act before it is brought into force. The Delhi Rent Act (Amendment) Bill, 1997 was accordingly introduced in the Rajya Sabha on 28.7.1997. The Amendment Bill provides for changes mainly pertaining to the clauses relating to the following:-

(i) Deemed rent;

(ii) Compulsory registration of tenancies;

(iii) Enhancement of rent;

(iv) Inherilability of tenancies in respect of non-residential premises; and

(v) Eviction of tenants.

विभिन्न संयंत्रों एवं परियोजनाओं में इस्पात की मांग

74. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत संयंत्रों, सीमेन्ट संयंत्रों, निर्माण संबंधी परियोजनाओं, जहाजरानी तथा रेल परियोजनाओं में इस्पात की कुल वास्तविक मांग कितनी रही है,

(ख) क्या इन क्षेत्रों को इस्पात की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं, और

(घ) रेलवे, विद्युत संयंत्रों, जहाजरानी तथा देश के अन्य क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार इस्पात की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की मांग का अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया जाता है, न कि विशिष्ट उपभोक्ता क्षेत्रों के आधार पर । गत्त तीन वर्षों के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की मांग और उत्पादन निम्न प्रकार रहा:-

(मात्रा: लाख टन में)

वर्ष	मांग	उत्पादन
1995-96	212.9	214.0
1996-97	221.2	227.2
1997-98	223.8	225.7

(अनन्तिम)

इस समय, इस्पात को अधिकांश मदों का कोई कमी नहीं है । उपभोक्ता क्षेत्रों के सभी खण्डों में इस्पात की पर्याप्त आपूर्ति/उपलब्धता है । मात्रा और गुणवत्ता की

दृष्टि से घरेलु उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नीति के अनुसार इस्पात की सभी मदों का निर्बाध रुप से आयात करने की अनुमति है । विगत 2 वर्षों में इस्पात का कई मदों पर आयात शुल्क में कमी की गई । तथापि, सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र घरेलु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहें हैं । इन प्रयासों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पादकता और उत्पादन में सुधार, उत्पादों का गुणवत्ता में सुधार करना तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरुप उत्पाद भिन्न को अपनाना शामिल है ।

Setting up of Aluminium Plants during Ninth Plan

*75. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to set up some Aluminium/Alumina Plants in the country during Ninth Plan;

(b) if so, the States where these plants would be set up;

(c) whether any such Aluminium/Alumina plant is going to be set up in Orissa;

(d) if so, the sites selected therefor; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH B AIS): (a) The Government have no proposal to set up any new Aluminium/Alumina Plants in the country in public/joint sector during the Ninth Five Year Plan. As per the industrial policy, the aluminium industry has been exempted from the provision of compulsory licensing with a view to encourage private investment in the aluminium sector.

(b) to (e) Does not arise in view of reply to part (a) above.

वाहन निर्माता कंपनियां

*76. **प्रो0 राम बख्श सिंह वर्मा :**
श्रीमती मालती शर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वाहन निर्माता कंपनियां कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वाहन निर्माता कंपनी द्वारा वर्ष-वार कितने-कितने वाहनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था; और

(ग) क्या प्रत्येक वाहन निर्माण कंपनी ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) देश में 29 वाहन निर्माता कंपनियां है । इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. यात्री कार और बहु-उपयोगों के वाहन निर्माता	13
2. वाणिज्यिक वाहन निर्माता	08
3. दुपहिया निर्माता	12
4. तिपहिया निर्माता	04

(कुछ कंपनियां एक से अधिक मद की निर्माता है)

(ख) और (ग) सरकार द्वारा वाहनों का विनिर्माण किए जाने हेतु वर्ष-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है और वाहनों का निर्माण किया जाना मांग और आपूर्ति की विपणन संचालित शक्तियों पर आधारित है । 1993-97 के वर्षों में आटोमोबाईल में लगभग 20% की औसतन दर से ऊधमी वृद्धि हुई है । वर्ष 1997-98 में मुख्यत: अर्थ-व्यवस्था में सामान्य गिरावट होने के कारण मांग में मंदी और इसके परिणामस्वरुप उत्पादन में कमी होने की स्थिति देखने में आयी है ।

Clearance of Sukhinda Chrome-Ore Mines

*77. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government had received any request from Government of Orissa for the clearance of Sukhinda Chrome-Ore Mines;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken thereon by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (c) The State Govt, of Orissa had sent a proposal dated 24th June, 1997 to the Ministry of Mines seeking approval for the grant of mining lease for chrome ore in Sukhindra Valley of Orissa over 50% of the balance area of 855.476 hects. which had become available for grant after the second renewal of the mining lease of TISCO for a reduced area, in favour of four parties, i.e. Indian Metal and Ferro Alloys (MFA)/Indiari Charge